Publication Name: Loksatya
Publication Date: 25/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 5
CCM: 275.28

Bharat Taxi to be in every city of the country

देश के हर शहर में होगी 'भारत टैक्सी'

मात्र 500 रुपये का शेयर लेकर कोई भी सारथी मालिकाना हक का भागीदार बन सकता है

- **तीन वर्ष का लगेगा समय, 'भारत टैक्सी' में सारथियों की अब तक की सारी चिंताओं का समाधान होगा**

नई दिल्ली, लोकसत्य। नई दिल्ली की उस दोपहर में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। देश के कोने-कोने से आए टैक्सी चालकों के बीच एक विचार आकार ले रहा था – श्रम करने वाला ही मुनाफे का असली हकदार हो। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, यह सोच के बदलाव की शुरुआत थी।

सहकारिता के असल योद्धा अमित शाह के विज़न के केंद्र में एक सीधा प्रश्न था सड़क पर दिन-रात मेहनत करने वाला व्यक्ति आखिर केवल कमिशन पर क्यों जिए? क्यों न वही मालिक बने? और यहीं से कहानी शुरू होती है 'ड्राइवर' से 'सारथी' बनने की।

शाह ने जिस सोच को सामने रखा, उसमें 'ड्राइवर' शब्द की जगह 'सारथी' को प्रतिष्ठा देने का संकल्प था। यह केवल शब्द परिवर्तन नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और साझेदारी की नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास था। सड़क पर पसीना बहाने वाला व्यक्ति केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि व्यवस्था का भागीदार और स्वाभिमान से भरा मालिक हो यही इस पहल का मूल भाव है।

अंत्योदय की राजनीति करने वाले अमित शाह की परिकल्पना में 'भारत टैक्सी' किसी निजी कंपनी की तरह अधिकतम लाभ कमाने की दौड़ में शामिल नहीं है। इसके केंद्र में वह व्यक्ति है जो रोज सड़कों पर पसीना बहाता है। 'भारत टैक्सी' की संरचना इस तरह गढ़ी गई है कि 500 रुपये का शेयर लेकर कोई भी सारथी मालिकाना हक का भागीदार बन सके। आने वाले तीन वर्षों में इसे देश के हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक पहुंचाने की रूपरेखा इस बात का संकेत है कि यह केवल एक सेवा नहीं, बल्कि सहकारिता के राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार है जो पीएम के नेतृत्व में सशक्त हुआ है।

देश के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की सोच

● देश के हर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने वाले अमित शाह की सोच इस मॉडल के राजस्व ढांचे में भी दिखाई देती है। कमाई का 80 प्रतिशत सीधे सारथियों के खाते में जितना चले, उतना कमाए। शेष 20 प्रतिशत भविष्य की पूँजी, ताकि व्यवस्था टिकाऊ बने। शुरुआती तीन वर्षों में विस्तार पर ध्यान और उसके बाद लाभ का समान वितरण यह संरचना बताती है कि लक्ष्य बाजार पर कब्जा नहीं, बल्कि स्थायी सहकारिता तंत्र खड़ा करना है।सहकारिता आंदोलन के रणनीतिक शिल्पी अमित शाह ने संरचना को इस प्रकार गढ़ा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथियों के लिए आरक्षित स्थान हों।